डिजिटल इंडिया मिशन की सेवाएं

प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अवसंरचना और सेवाएं

1. **हाई स्पीड इंटरनेट मुख्य सुविधा के रूप में**
   - जैसे पानी और बिजली की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर नागरिक को तेज़ इंटरनेट का लाभ मिलना चाहिए। यह डिजिटल युग में जुड़ने और काम करने की एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है।
2. **जन्म से लेकर अंत तक डिजिटल पहचान**
   - हर व्यक्ति को एक जीवन भर की डिजिटल पहचान दी जाए, जिससे वे सभी सरकारी और निजी सेवाओं तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकें।
3. **मोबाइल फोन और बैंक खाता**
   - मोबाइल फोन और बैंक खाते नागरिकों को संचार और आर्थिक सेवाओं तक पहुँचने में मदद करते हैं, जिससे वे डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनते हैं।
4. **सामान्य सेवा केंद्र की आसान पहुंच**
   - ऐसे केंद्रों का नेटवर्क, जहां से लोग सरकारी और डिजिटल सेवाएं ले सकते हैं, विशेषकर वे लोग जिनके पास खुद के डिजिटल उपकरण नहीं हैं।
5. **सार्वजनिक क्लाउड पर निजी स्थान**
   - एक सुरक्षित डिजिटल स्थान, जहां व्यक्ति अपने डिजिटल दस्तावेज़ सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार साझा कर सकते हैं।
6. **सुरक्षित साइबर-स्पेस**
   - एक ऐसा डिजिटल वातावरण जो सभी को साइबर खतरों से बचाता है और गोपनीयता बनाए रखता है, ताकि लोग सुरक्षित रूप से ऑनलाइन कार्य कर सकें।

इन सुविधाओं से नागरिकों को एक सशक्त और सुरक्षित डिजिटल जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है।

सरल और सुलभ डिजिटल शासन

1. **सामंजस्यपूर्ण डिजिटल सेवाएं**
   - विभिन्न विभागों के बीच सेवाएं जुड़ी हों ताकि नागरिकों को एक आसान और एकीकृत डिजिटल अनुभव मिले।
2. **रियल-टाइम ऑनलाइन सेवाएं**
   - सभी सेवाएं ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हों, ताकि नागरिक तुरंत और तेजी से इनका लाभ उठा सकें।
3. **क्लाउड पर नागरिक अधिकारों की पहुंच**
   - नागरिकों के सभी अधिकार और सेवाएं क्लाउड पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध हों ताकि आसानी से पहुंचा जा सके।
4. **व्यवसाय करने में आसानी**
   - डिजिटल रूप से प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि व्यवसाय शुरू करना और चलाना आसान हो जाए।
5. **इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस लेनदेन**
   - भुगतान और लेन-देन डिजिटल और नकदी रहित तरीके से हो, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़े।
6. **निर्णय के लिए जीआईएस का उपयोग**
   - विकास और योजनाओं के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग, ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सकें।

इन सुविधाओं से डिजिटल और व्यवसायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

1. **सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता**
   - हर व्यक्ति को डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास के साथ काम करने की क्षमता देना। इसके लिए डिजिटल शिक्षा और समझ बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि सभी लोग डिजिटल साधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें।
2. **सभी के लिए सुलभ डिजिटल संसाधन**
   - यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल जानकारी और सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हों। इसमें विशेषकर उन लोगों का ध्यान रखना है, जिनके पास डिजिटल संसाधनों की सीमित पहुंच है।
3. **क्लाउड के माध्यम से दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र सुलभ**
   - सभी जरूरी दस्तावेज़ और प्रमाणपत्रों को क्लाउड पर स्टोर करना, ताकि किसी भी समय और कहीं से भी इन्हें सुरक्षित रूप से देखा जा सके।
4. **भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधन**
   - अलग-अलग भारतीय भाषाओं में डिजिटल जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराना, ताकि सभी नागरिक इसे आसानी से समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें।
5. **सहभागी शासन के लिए सहयोगात्मक डिजिटल मंच**

- ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाना, जहाँ नागरिक शासन में अपनी राय और सुझाव दे सकें। इससे पारदर्शिता और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

6. **क्लाउड के माध्यम से सभी अधिकारों की पोर्टेबिलिटी**
   - नागरिकों के सभी अधिकार और लाभ क्लाउड पर उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी सुविधानुसार कभी भी और कहीं भी इनका लाभ उठा सकें।

इस तरह, इन सुविधाओं से नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाया जा सकता है।

डिजिटल इंडिया मिशन के प्रमुख फोकस क्षेत्र

नवाचार

डिजिटल इंडिया तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने, वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल समाधानों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने में सबसे आगे है। हम नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोग करते हैं जो भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनाने में सक्षम बनाता है।

डिजिटल समावेशन और पहुंच

हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि डिजिटल सेवाएँ सभी के लिए सुलभ हों, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों, दिव्यांग व्यक्तियों और ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। लक्षित पहलों के माध्यम से, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य प्रौद्योगिकी को प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का एक सक्षमकर्ता बनाना है।

क्षमता निर्माण और कौशल विकास

डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल के महत्व को पहचानते हुए, डिजिटल इंडिया सक्रिय रूप से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में लगा हुआ है जो नागरिकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करते हैं। हम भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा का समर्थन करने वाले प्रतिभा पूल को बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर काम करते हैं।

डिजिटल उद्यमिता को समर्थन

हम शासन और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाते हैं, जिससे सार्वजनिक सेवाएँ अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बन जाती हैं। ई-गवर्नेंस पहलों को अपनाने के ज़रिए, डिजिटल इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सरकारी सेवाओं के साथ सहजता से बातचीत कर सकें।

सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी

हम शासन और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाते हैं, जिससे सार्वजनिक सेवाएँ अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बन जाती हैं। ई-गवर्नेंस पहलों को अपनाने के ज़रिए, डिजिटल इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सरकारी सेवाओं के साथ सहजता से बातचीत कर सकें।

डिजिटल इंडिया मिशन के लाभ

डिजिटल इंडिया मिशन एक ऐसी पहल है जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में से एक है। डिजिटल अपनाने के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 2 देशों में शुमार है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 तक 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाने की संभावना है।

डिजिटल इंडिया के कुछ लाभ इस प्रकार हैं -

- ई-गवर्नेंस से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में वृद्धि हुई है।
- भारत नेट कार्यक्रम के अंतर्गत 2,74,246 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ने 1.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा है।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत एक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) बनाया गया है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुँच प्रदान करता है। कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से, CSC ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन और अन्य सरकारी और निजी सेवाओं से संबंधित मल्टीमीडिया सामग्री प्रदान करते हैं।
- सौर प्रकाश व्यवस्था, एलईडी असेंबली इकाई, सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई और वाई-फाई चौपाल जैसी अच्छी तरह से सुसज्जित सुविधाओं के साथ डिजिटल गांवों की स्थापना।
- इंटरनेट डेटा का उपयोग सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच 64% तक पहुंच गई है।
- डिजिलॉकर्स – इस प्रमुख पहल का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का 'डिजिटल सशक्तिकरण' करना है

Thanks From Team X

Keep Learning And Keep Earning !